

1	2	3	4	
5 Forest	6,06,33,000	12,50,000	30,31,66,000	62,50,000
6 Cooperation	3,84,96,000	28,86,71,000	9,24,79,000	144,33,54,000
7 Department of Food	118,84,79,000	4,22,85,000	594,23,94,000	21,14,28,000
8 Department of Agricultural Research and Education	13,47,000		67,36,000	
9 Payments to Indian Council of Agricultural Research	18,86,37,000		94,31,83,000	
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT				
75 Ministry of Rural Development	75,03,82,000	8,20,000	375,10,11,000	41,00,000

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I call upon Mr. Bhim Singh to speak.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): When the Ministry's Demands for Grants are taken up, at least the senior Minister should be present.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): He is coming, Sir.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): What is coming? The Minister should be present here. Don't denigrate the Parliament like that. We will not allow this to be discussed. This is denigration of the House. This has never happened. Will you cite me any example? They are not taking the House very seriously. The Grants are here for discussion and the Minister is absent. I can understand after the grants are moved, the Minister being absent for a short while for some pressing appointment, but in the beginning when the Demands are presented, the Minister should be present. This is a serious lapse and we cannot allow this to happen.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister of State for Agriculture is here. The Minister is coming... (Interruptions)

SHRI CHANDRAJIT YADAV: It is not a question of the State Minister being here. This is totally against the established practice of the House. This is not taking the House most seriously. Even the Minister should cancel his most important appointments to be present in Parliament.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): He is engaged in a committee meeting, Sir.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: We will not accept this explanation. We know that Ministers have always cancelled their most important meetings even abroad whenever their grants come up for discussion. I know from personal knowledge that they cancel their meetings even abroad and they have seen to it that they should be present when their Demands come. Now, the Minister is in the capital and they say that he is attending a meeting. This is a most non-serious attitude towards the House and I think you should not agree to this. You please adjourn the House till the Minister comes... Why are you taking it so lightly?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND

HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): The Minister of State is here.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: What is this Minister of State?

MR. DEPUTY SPEAKER: He has already explained.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: What is it he has explained? We will not allow this to go on.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: The hon. Minister is coming. There is no question of denigration of the Parliament. He is coming. The Minister of State is here; the Deputy Ministers are here. Everybody is here. The Agriculture Minister will be coming.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: From the very beginning the absence of the Minister is a very serious matter. This is not the correct way.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has just now said that he is coming. Mr. Bhim Singh. (Interruptions) You have expressed your opinion. He has already explained the position.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: I know the Parliamentary Affairs Minister keeps quiet. I know he is embarrassed. It is a serious lapse on the part of the Agriculture Minister.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Alternatively, Shri Swaminathan can walk out of the House in protest.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhim Singh. I think he has explained it. The purpose has been served. Let Mr. Bhim Singh speak. (Interruptions)

SHRI CHANDRAJIT YADAV: If you do not agree, then I will walk out with your permission.

श्री राजेश कुमार फीरोजाबाद : हम वाकआउट कर रहे हैं, आप अपना कार्यवाही चलाइये।

MP DEPUTY-SPEAKER: You need not take my permission at all. Nobody

need take my permission. Shri Bhim Singh.

17.12 hrs.

(Shri Chandrajit Yadav and other hon. Members then left the House)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): You express your resentment. In the past the Speaker has done this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. I have already called Shri Bhim Singh.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is not all right.

At least you express your displeasure so that they will take note of it for the future.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhim Singh, you are to initiate the discussion. You please start.

(Interruptions)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Who will hear? Let the hon. Minister come here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhim Singh, are you going to take the initiative to speak? The request has come from you. That is why I have called you. Are you going to speak or not? Otherwise I shall call the next speaker. If you are going to speak, I shall call the next Member.

श्री भीम सिंह मुसन्नू : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम निवेदन यह है कि मंत्री कहाँ दण्ड आये नहीं है, मैं आपके द्वारा किस को अपनी बात सुनाऊँ

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: All of you please sit down.

(Interruptions)**

Let this not go on record. If you do not speak, I shall call the next Member.

[Mr. Deputy Speaker]

Government has already taken note of the sentiments expressed by the hon. Member. Don't politicalise everything.

Mr Bhim Singh was on his legs. He has already started speaking. Since Mr. Bhim Singh has made a special request, I have called him to speak. Are you going to speak?

(Interruptions)

SHRI BHIM SINGH: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why are you worried? You may speak. It will be recorded. Whatever you speak will be recorded.

PROF. RUP CHAND PAL: (Hooghly): Why are you insisting on this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not question me. Please take your seat if you want. Mr Bhim Singh.

17.14 hrs.

(Prof. Rup Chand Pal and some other hon. Members then left the House).

श्री भीम सिंह (झुन्डुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, मैंने जो बातें कहनी हैं, वे किसको सुनाऊं ? यह तो अरण्य-रोदनक के बराबर होगा। मैं आपके आदेश के अनुसार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बोलना अरण्य-रोदन के बराबर नहीं होगा। वह सरकार तक पहुंचेगा। मिनिस्टर साहब पधारे हैं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : वह आ तो गये हैं। उनसे माफ़ी मंगवाइए।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक प्रति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : ये जो चार महानुभाव बैठे हैं, क्या वे मेरे साथी नहीं हैं ? वे भी मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: They wanted to see you physically.

श्री भीम सिंह : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सब से मुख्य कार्य यह रहा है कि वह देश को ज्यादा से ज्यादा अन्न दे

और सस्ते दामों पर दे। पिछले दो सालों के दौरान हर एक डीबेट में मंत्री महोदय यह फरमाते आ रहे हैं कि देश का प्राइवशन बढ़ रहा है और प्राइसिज काफ़ी काबू में है। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट आफ फ़ूड के आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सरकार ने 1978-79 और 98-81 के प्राइवशन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	1978-79	1980-81
	(मिलियन टन)	
चावल	53.77	53.23
गेहूँ	35.51	36.46
मल्लिसज	12.18	11.17
टोटल फ़ूडग्रेन्ज	131.90	129.87
चना	5.74	4.65
आयल सीड्स	9.35	8.34
शुगरकेन	15.73	15.40
	वेल्ज	वेल्ज
काटन	7.96	7.60

जहां फ़ूडग्रेन्ज का प्राइवशन कम हुआ है, वहां चीजों के भाव आसमान को छूने लगे हैं। दिल्ली देश की कैपिटल है, उसके भावों को ले लीजिये। गेहूँ का भाव 1980 में 1.64 रुपये पर के जी था, जो 1981 में बढ़ कर 9.99 रुपये पर-के जी हो गया और हाल में 2.00 रुपये से भी कहीं ऊपर चला गया है। मूंग का भाव 1980 में 4.85 रुपये था, जो 1981 में बढ़कर 5.46 रुपये हो गया। चने का भाव 1980 में 4.31 रुपये था, जो 1981 में 5.36 रुपये हो गया। सरसों का भाव 15.00 रुपये पर-के जी से बढ़कर 15.39 रुपये हो गया और तिल का भाव जुलाई, 1981 में 15.82 रुपये से बढ़कर अगस्त में 16.23 रुपये ये तक पहुंच गया है। प्राइसिज बढ़ रही है और प्राइवशन घटता जा रहा है। इस के बावजूद सरकार कहती है कि हम प्रगति कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार मैं होलसेल प्राइस इन्डेक्स भी देना चाहूंगा। इस में फूडग्रेन्स के लिये 1980 की फ्रीगर्स दी गई है और पल्सेज के लिये 1981 की फ्रीगर्स दी गई है, जनवरी से लेकर दिसम्बर तक की। फूडग्रेन्स में 1980 में 225.8 से बढ़कर 235.1 पर चली गई। इसी तरह से पल्सेज में 326 से बढ़कर इन्डेक्स 360 पर चला गया इसी तरह से सारे के सारे फूडग्रेन्स, एडिबिल ग्रायल्ज और पल्सेज के भाव ऊंचे जा रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने पिछले साल दोनों डिक्ट्स में प्रामिस किया था कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन आपकी फ्रीगर्स के मुताबिक ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन गिरा है और भाव ऊंचे जा रहे हैं।

अब इस बात को एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रोडक्शन दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो यह कि आप कास्तकार को अच्छे किस्म का बीज मोहैया करें। साथ ही अच्छे किस्म का बीज आप टाइम पर दें। अगर टाइम निकल जाता है और इम्प्रूव्ड वैरायटी की लैट सोइंग होगी तो प्रोडक्शन डेटेरियारेट होता जायेगा। मैंने निवेदन किया कि हम एन एस सी के किसी स्टोर पर भी जाते हैं तो वहां पर वे वही पुराने घिसे-पिटे बीज लिये बैठे हैं जैसे गेहू में कल्याण सोना है, और और 21 है या सोनालिका है—इसके बीज आपको मिलेंगे। आप रिसर्च पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आई सी ए और और दूसरी एजेंसियों के जरिये से, और आप कहते भी हैं कि नयी नयी वैरायटीज आप ईजाद कर रहे हैं लेकिन अगर वह वैरायटीज लैवाटेरीज में ही रह जायें या स्टोर्स में ही पड़ी रहे और किसान तक न पहुंचे तो जितना भी खर्चा आपने रिसर्च पर किया है वह आप समझ लीजिये कि बेकार ही गया। इस-

लिये जितनी भी इम्प्रूव्ड वैरायटीज हों वह एन एस सी के जरिये से सोईंग टाइम पर जरूर एवलेवल होनी चाहिए। आपको इस बात की निगरानी रखनी चाहिए कि वहां स्टॉक्स पहुंचते हैं या नहीं।

इसके अलावा सोईंग टाइम पर फटिलाइजर की बहुत जरूरत होती है। फटिलाइजर के लिये पिछले साल आपने जो कोशिश की उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपने फटिलाइजर मोहैया करने का बहुत प्रयास किया लेकिन साथ ही साथ इसमें जो वाटलनैक्स है वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। कुछ फटिलाइजर फैक्ट्रीज की यह प्रैक्टिस है—मैं नाम लेकर बताना चाहूंगा—श्रीराम फटिलाइजर्स, कोटा अक्टूबर के महीने में फैक्ट्री बन्द कर देते हैं और कहते हैं कि मैन्टिनेंस के लिये बन्द की गई है। आप जानते हैं कि अक्टूबर-नवम्बर के महीने में ही सबसे ज्यादा फटिलाइजर की जरूरत होती है। अगर मैन्टिनेंस के लिये फैक्ट्री बन्द ही करनी हो तो मई जून के महीने में बन्द की जा सकती है जबकि फटिलाइजर की डिमांड बहुत कम रह जाती है। अक्टूबर के महीने में फैक्ट्री बन्द करने का नतीजा यह होता है कि फटिलाइजर ब्लैक में मिलता है। प्रोडक्शन के लिये यह जो इनपुट्स है इनके दाम कितने बढ़ गये हैं, यह मैं बताना चाहूंगा। ए पी सी ने तो दाम कम निश्चित किये लेकिन इनपुट्स की कीमतें बहुत बढ़ गई। मिसाल के तौर पर यूरिया एक समय में 72 रुपये कट्टा बिकाता था जो अब 125 रुपये तक चला गया है। सुपर फास्फट का भाव 36 रुपये से बढ़कर 51 रुपये हो गया है। इसी प्रकार से पेस्टिसाइड्स में मुख्य रूप से बी एच सी के दाम वहां से कहां पहुंच गये हैं ?

[श्री भीम सिंह]

जहां तक बिजली का संबंध है, राजस्थान में 6 घंटे के हिसाब से प्लैट रेट कैलकुलेट किया गया था लेकिन उसके बजाये 4 घंटे ही आप बिजली दे रहे हैं। इस तरह से प्रति यूनिट प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई। काश्तकार से आपने जितना पैसा बिजली के लिये लिया उसके कम्पेरीजन में उसको कम पानी मिला जिससे उसकी प्रोडक्शन भी कम हो गई।

इसी तरह से पैस्टिसाइड्स की एवले-विलिटी ठीक रहे और उसकी नो-हाऊ किसान तक पहुंच जाये तो किसान अच्छी फसल उगा लेता है। अगर काश्तकार इन्सैक्टिसाइड्स और पैस्टिसाइड्स का प्रापर यूज करके इन्सैक्ट्स और दूसरी बीमारियों को कंट्रोल नहीं करता है तो भी वह प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकता है। पहले एन एस सी की तरफ से जो सीड मिलता था उसमें से एक पर्ची निकलती थी जिसपर सारा नो-हाऊ लिखा होता था कि कैसे उसको यूज किया जाये। लेकिन अब मैं समझता हूं एकोनामी मेजर ही होगा जिसकी वजह से किसी भी थैली में कोई भी लिफलेट नहीं निकल रहा है। काश्तकार एक्फीरयेंस हैं, तो ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा उन लोगो को जानकारी दी जानी चाहिए। रिसर्च स्कालर्स के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा—दे शुड गो लैंड टु लैंड—जमीन पर जायेंगे तभी तो बता पायेंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है।

मैं एनीमल हेल्थेन्डी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था। आज आप व्हाइट रिवोल्यूशन करने जा रहे हैं, दूध का

उत्पादन करने जा रहे हैं। उसमें आपके कारपोरेशन्स जो काश्तकारों को पैसा देते हैं, वह भी फैंट परसेंटेंज के बेस पर देते हैं। आपकी जो इम्प्रूव्ड काउज की वैरायटीज हैं, जैसे होस्टिन हैं, प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और टोटल सोलिड अदर फैन पैट वेस पर जैसे कि दूसरी कंट्रीज में पैसा दिया जाता है, यदि उस तरह से देंगे तो काश्तकारों को रिस्पूनरेटिव पैसा मिलेगा। अब तो फीड कास्ट भी बढ़ गई है। पहले के मुकाबले में फीडिंग कास्ट अब ज्यादा बढ़ गई है। फैंट परसेंटेंज भी अब इतना नहीं मिल पाता है।

इसके आलावा मैं ए० आई० सेंटर्स के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इस में आपने नये नये लडकों को भर्ती कर लिया है। इस प्रकार गांयों को या तो बिगाड़ दिया जाता है या फिर वे फर्टिलाइज नहीं हो पाती हैं। बीमारी लग जाती है। इन्फेक्शन लग जाता है। इस में कम से कम एक्सपीरियेंसड आदमी होना चाहिए। जैसे कि आप के एफ०-1 और एफ-11 जानवर हैं, जो कि बहुत ही कास्टली जानवर हैं। तीन-तीन, चार-चार हजार के जानवर हैं। वे पहले या दूसरे लैक्टेसन में जैनेटिकल प्रोडक्शन न दे सकें, तो कितना नुकसान होगा। आपका जो बूस्ट आया है वह एफ-11 में जा कर रूकावट खा गया। इसका मूल कारण यह है कि आपकी जो ओरिजिनल इन्डिजिनस जो ब्रीड थी, वह एफ-1 और एफ-11 में आसिंग प्रोग्राम में चली गई और इन्डिजिनस ब्रीड पर जो तवज्जह दी जानी चाहिए थी उसके इवलेपमेंट के लिये जो तवज्जह जानी चाहिए थी, उसमें कमी आ गई। जो गाय एक लोटा दूध देती है, उसके क्रास करने से रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आयेगा या जो कम से कम दस किलो दूध देती है, उसके क्रास करने से दूध

ज्यादा आयेगा। साहिवाल एक ब्रीड थी जो अब पाकिस्तान में चली गई, लेकिन साहिवाल के लम्बू-भंगू की कमी नहीं है, लेकिन उनके लिये कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा लिलितगो के टाइम में करनाल में उन के लिये काम हुआ था। अब इस के स्टॉक को आपने सूरतगढ़ में भेज दिया और अब सूरतगढ़ में कोई वर्क नहीं हो रहा है। जो स्टॉक है, वही स्टॉक है। यदि स्मॉलिंग हो कर पाकिस्तान से कोई आते हैं, अकाल पड़ता है, तो उस वक्त यह प्रोडक्शन हो सकता है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्डिजिनस ब्रीड पर कन्सन्ट्रेंट करें, उस पर कन्सन्ट्रेंट करने से आपका व्हाइट रिवोल्यूशन सैक्सस-फल होगा।

तीसरे मैं मिल्क आर्गेनिजेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा इस संबंध में एक शिकायत भी है। आप शहर के आदमियों को दूध देकर खूब मोटा लम्बा तगड़ा बनाना चाहते हैं, और देहात की हैल्थ दिन पर दिन गिरती जा रही है। फारेन कंट्रीज की जो डैयरी कारपोरेशन्स हैं, वे खुद कैटिल का स्टॉकमैटेन करती हैं और मिल्क इकट्ठा करती हैं। लेकिन आप सारा का सारा दूध देहातों से खींच करके दिल्ली को देना चाहते हैं, कलकत्ता को देना चाहते हैं और बम्बई को देना चाहते हैं और देहात के आदमी की हैल्थ क्या हो गई है। पहले यह इकानामी थी कि थोड़ा बहुत दूध हलवाई को बेच देते थे और बाकी छाछ बिलोते थे तथा बच्चों को सुबह छाछ से रोटी देते थे, दही देते थे। लेकिन अब चाय थोड़ी सफेद धोली करके दे देते हैं, उससे देहात के आदमियों की हैल्थ नहीं गिरेगी तो क्या होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रोडक्शन तो बढ़ायें लेकिन उस प्रोडक्शन का सर्टेन पोर्शन यहां लें और सर्टेन पोर्शन देहात

के लिए दें, तो वहां भी दूध उपलब्ध हो सकेगा और बच्चे डेवलप हो सकेंगे।

तीसरी बात मैं रिसर्च इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में कहना चाहता हूँ। आई. सी. ए. आर. और दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स, जिनके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था वहां प्रोमोशन्स को लेकर उनको पूरा पैट्रोनेज नहीं मिलता है। आपस में झगड़े चलते हैं, उनके वर्क के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलता है और आपके साइंटिस्ट डिस्-सैटिसफाइड हैं। जब तक इनके यहां प्रोमोशन्स के लिए या दूसरे झगड़ों के लिए ऐसे आदमी नहीं रखेंगे जो काम्प्यूटेट हों, जो सिफारिश बगैर आए हों और जिन में काबलियत हो, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, उन को एन्क्रेजमेंट मिलना चाहिए। तभी कुछ रिजल्ट आ सकेंगे।

आज आप की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, उन की हालत भी बहुत खराब है। आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वे झगड़े के अखाड़े बनी हुई हैं। वाइस चान्सलर को पीट डालते हैं और आपस में लड़कों में लड़ाई होती है एग्जामिनेशन्स को रोकने के लिए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज झगड़े के अखाड़े बना दी गई हैं। इन में प्रोपर टाइप के वाइस चान्सलर्स को रखा जाए, जो पार्टी पालीटिक्स और स्टाफ की पालीटिक्स में न पड़ें और बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें और इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को फीड करने के लिए एग्रीकल्चरल स्कूल्स की बहुत कमी है। अब मैं राजस्थान के बारे में आप से निवेदन कर सकता हूँ। वहां एक अजमेर कालेज है। वह उदयपुर यूनिवर्सिटी का पार्ट है क्योंकि उदयपुर यूनिवर्सिटी इज बी ओनली यूनिवर्सिटी। आज गंगा नगर का जो एरिया है, उस के बारे में सोचना चाहिए। राजस्थान केनाल से वह एरिया इन्डिया की ग्रैनरी

[श्री श्रीम सिंह]

बनने जा रहा है और उस ग्रैनरी एरिया में कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं। उदयपुर के लिए तो मैं समझा हूँ कि माइनिंग की यूनिवर्सिटी होती तो वह ज्यादा फिट करती लेकिन वह उस जमाने में किसी कारण बन गई पर आज गंगा नगर जस्टिफाई करता है ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरी स्टेट्स में भी जहाँ ग्रैनरी एरिया है या 'केनाल एरिया' है, वहाँ पर इस तरह की यूनिवर्सिटी कायम करें।

तीसरा मैं आप से निवेदन करना चाहूँगा बिजली के बारे में। इस के लिए काफी कोशिश की जा रही है कि बिजली टाइम पर मिले। इस साल भी राजस्थान के ग्रन्डर अग्र बिजली के भरोसे रहते, तो सारा प्रोडक्शन ही खत्म हो जाता। वह तो भगवान की कृपा कास्तकार पर हुई कि तीन चार बार टाइम टू टाइम अच्छी बरसात हो गई और उस से अच्छा प्रोडक्शन हुआ, अच्छी फसल हो गई। अब घाबीर में आ कर कुछ ओले बगैरह पड़ गये, जिन से कुछ नुकसान हुआ है। कास्तकार के सामने यह प्रश्नवाचक चिह्न बना रहता है कि इस साल तो काम चल सके, अगले साल क्या होगा। रावत-आटा में जो एटोमिक पावर प्लांट है, वह राजस्थान के लिए एक केन्सर बना हुआ है। उस से कभी बिजली मिलती है और कभी नहीं। उस के भरोसे राजस्थान का किसान जिनका नहीं रह सकता। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप बिजली की व्यवस्था ठीक से करें और राजस्थान के कास्तकार को बिजली के लिए एश्योर करें कि टाइम पर उसे बिजली मिलेगी। अब आप यह उम्मीद मत कीजिए कि वहाँ का कास्तकार फिर से चरस पर स्विच आन कर

लेगा। वह अब चरस नहीं चलाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर आज एक हाईली टेक्निकल इंडस्ट्री हो गई है।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप के यहाँ पोर्टेबिल है, उस को टेप कीजिए। ग्रन्डरगाउन्ड वाटर सर्वे कराइए। मैंने पिछली डिवेट में भी इस के बारे में अर्ज किया था एण्ड यू वर काइंड एनफ टू गो टू जयपुर। आप जयपुर गये थे और वहाँ पर आप ने राजस्थान गवर्नमेंट को कहा था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी कहा था कि जहाँ पोर्टेबिल है, वहाँ पर ट्यूबवैल्स बनें। वहाँ पर ट्यूबवैल्स कापॉरेशन हों। अगर यू. पी. में ट्यूबवैल्स कापॉरेशन हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं बन सकता? राजस्थान में सीलिंग आने के बाद यूनिट इतने छोटे हो गये हैं कि वहाँ पर कास्तकार अपने खर्च से किसी भी हालत में ट्यूबवैल नहीं लगा सकता। ट्यूबवैल की मोटर खराब हो जाती है या उसे का पम्प जल जाता है तो उसे बाहर जा कर ठीक कराया पड़ता है और हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आप ट्यूबवैल कापॉरेशन बनाइए और जो पानी आप ट्यूबवैल बन कर दें उसे पानी का पैसा चार्ज कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा एरिया आप कवर कीजिए।

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर के कास्तकार को उस के उत्पादन की पूरी रेमूनरिटेब प्रॉइस जब मिलेगी, तभी एक आधमी एग्रीकल्चरलिस्ट के जाब में रहेगा। अगर उसको पूरा मार्जिन ग्राफ प्रॉफिट होगा, तभी वह इस की करेगा। एक लड़के ने बी. एस. सी. पास किया है और दूसरे ने बी. ए. पास किया और वह आई. ए. एस. या दूसरी

सबिस में जाता है, जहाँ उस को दो, ढाई हजार रुपये तन्द्वाह मिलती है, तो जो ग्रेजुएट आप से एम्प्लायमेंट सीक किये बगैर खुद के फार्म में सेल्फ-एम्प्लायड है, तो उस के पास भी कम से कम इतना साधन होना चाहिए कि वह कम से कम दो, ढाई हजार रुपया कमा सके। जब उसको ऐसा मौका मिलेगा, तभी जो इन्टेलिजेंसिया है, जो यूथ है, वह देहात में बैठेगा और खेती के प्रोफेशन को अपनाएगा और वहाँ जाने के बाद देहात को चमन कर देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जितने भी इंटेलिजेंट लड़के हैं, वे शहरों की तरफ भागेंगे और जो ग्रनपंड हैं, नाका-बिल हैं, वे देहातों में रहेंगे।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

Ministry of Agriculture

SHRI M. RAMANNA RAI (Kasargod): I beg to move.

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[Need for constituting a national committee for evolving a national price policy for various commodities, industrial as well as agricultural (3)]

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[Need for increased supply of sugar through fair price shops by acquiring 75 per cent of the sugar manufactured by sugar mills. (4)].

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[Need to give provident fund benefit to workers of FCI godowns at Kuthuram. (5)].

"That the Demand under the Head Fisheries be reduced by Rs. 100."

[Need to develop minor ports like Kasargod, Baliapatnam, Beypore, Ponnani, Cramganore as fishing harbours. (37)].

"That the Demand under the Head Fisheries be reduced by Rs. 100."

[Need to provide funds for mid-day meal and other educational facilities to the children of fishermen. (38)]

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur): I beg to move.

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100."

[Need to check the spread of outbreak of rinderpest in Delhi causing heavy losses. (57)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100.*"

[Need to effectively register valuable indigenous breeds. (58)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100."

[Need to set up semen banks of proven sires of different cattle and buffalo breeds in the country. (59)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100."

[Need to locate proven sires of important dairy breeds. (60)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100."

[Need to check the misdirection in the activities of Dairy Development Board. (61)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100."

[Need for proper implementation of Operation Flood I and II projects. (62)].

[Prof. Ajit Kumar] [ta]

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100." (58)

[Need to avoid dependence on foreign aid and personnel for training of dairy personnel for which indigenous facilities are available. (63)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100." (59)

[Failure to safeguard indigenous milk production from gift imports of milk products. (64)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100." (60)

[Need for indigenous manufacture of FMD by Government units such as IVRI, Bangalore and BAIF, Pune. (65)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100." (61)

[Need to cut down heavy overheads on machinery in DMUs leading to diversion of funds from production programmes. (66)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100." (62)

[Need to implement properly dairy projects and other commercial ventures such as FMD. (67)].

"That the Demand under the Head Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by Rs. 100." (63)

[Need to give proper guidance to Dairy Development Board and Indian Dairy Corporation. (68)].

"That the Demand under the Head Department of Agricultural Research and Education be reduced by Rs. 100." (64)

[Failure to ensure effective working of the ICAR and ASRE resulting in misbandling of scientists sent on deputation and training abroad. (69)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (70)

[Failure to develop new varieties in crops such as pulses and oilseeds. (70)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (71)

[Failure to lead the ICAR into constructive activities and to create environment for scientific work and activity. (71)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (72)

[Failure to re-organise Agriculture Scientists Recruitment Board on sound lines. (72)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (73)

[Failure to utilise cess funds for research work in ICAR. (73)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (74)

[Failure to step up production of various vaccines by IVRI. (74)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (75)

[Failure to accelerate milk production and processing research activities for ensuring speedy dairy development. (75)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (76)

[Failure to have increased food production from dryland. (76)].

"That the Demand under the Head Payments to Indian Council of Agricultural Research be reduced by Rs. 100." (77)

[Failure to inquire into large-scale death of sheep in C.S.W.R. (77)].

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Cooperation be reduced by Rs. 100."

[Need to provide incentive to farmers to bring more area under cultivation of edible oils and pulses. (88)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to ban cultivation of Kesari Dal. (89)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to supply improved quality seeds by N.S.C. to farmers well in time. (90)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to check malpractices in State Farms Corporation. (91)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to improve the per hectare yield of crops. (92)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Failure of Agricultural Price Commission to fix the prices of agricultural produce after studying all aspects at par with the industrial produce. (93)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to utilise land and water resources effectively for improving per hectare yield. (94)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to reduce the prices of fertilizers, seeds insecticides and agricultural implements. (95)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to increase the number of livestock needed for agricultural activities. (96)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need for proper co-ordination among various agencies responsible for improving agriculture. (97)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to ensure remunerative prices for agricultural produce. (98)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to reserve seats in institutions of higher education and research in agriculture for sons of agriculturists and agricultural labour. (99)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to make arrangements for storage of foodgrains at farmers level. (100)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to create storage capacity for storing perishable agricultural products at farmers' level. (101)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to fix remunerative prices for sugarcane, groundnut, gram, wheat, jawar, mustard, soyabean, moong and urad. (102)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need for making better arrangements for marketing of perishable agricultural produce like vegetables and fruits. (103)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need for arranging export of perishable agricultural products like vegetables and fruits. (104)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Prof. Ajit Kumar Mehta]

[Need to include agricultural experts in Agricultural prices Commission. (105)].

SHRI BHIM SINGH (Jhunjunu): I beg to move.

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[Need to check malpractices in NAFED. (78)].

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[Failure of Agricultural Price Commission to fix the agricultural prices after studying all aspects of agriculture. (79)].

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[Need to achieve the targets of food production, cereals, oil seeds and pulses. (80)].

"That the Demand under the Head Department of Agriculture and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[Need to give remunerative prices for sugarcane, groundnut, gram, wheat, coriander, chilli, jawar, mustard, soya-bean, moong and urad. (81)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to meet the requirements of seeds and their supply to farmers at proper time and to release improved varieties of seeds to them. (82)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to evolve effective and economical insecticides to control white grub. (83)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to make adequate milk collection from rural areas to meet the increasing demand for milk. (84)].

"That the Demand under the Head Department of Food be reduced by Rs. 100."

[Need to take over wholesale trade in foodgrains to ensure distribution at controlled prices through a network of public distribution system. (86)].

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): I beg to move.

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to increase the production of pulses, vegetables and oil seeds. (110)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to give more assistance to farmers for buying cows, buffaloes and cattle feed to increase milk production. (111)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to give remunerative prices to farmers for their agricultural commodities by eliminating middle-men (112)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to provide financial assistance to farmers at their doors through rural banks. (113)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to popularise the bio-gas in rural areas to save fuel and manure. (114)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to supply chemical manure to farmers at lower prices. (115)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to encourage farmers to use more and more animal manure and green manure. (116)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to supply good quality seeds to farmers. (117)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to provide insecticides to farmers to remove pests and give proper storing facilities to check waste by rats. (118)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to develop fish culture in rural areas. (119)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to provide assistance to farmers to have subsidiary jobs like sericulture, bee-keeping, poultry farming, mixed farming and dairy farming to become economically strong. (120)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to introduce crop insurance. (121)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to provide to the farmers the techniques of dry farming and rotation of crops. (122)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to encourage co-operative farming. (123)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to check the adulteration of sericulture products to help farmers to get better price. (124)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to give better veterinary facilities in rural areas. (125)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to preserve and protect wild animals which are rapidly disappearing. (126)].

"That the Demand under the Head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[Need to free agriculturists from the clutches of money lenders. (127)].

"That the Demand under the Head Forest be reduced by Rs. 100."

[Need to conserve existing forests and take up vigorous afforestation work. (128)].

Ministry of Rural Development

SHRI T. R. SHAMANNA: I beg to move.

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to strengthen and expand coverage of Integrated Rural Development and National Rural Employment Programmes. (18)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to rehabilitate bonded labourers in rural areas by giving them regular work and wages. (19)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to complete the programme to supply drinking water to villages without further delay. (20)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need for building simple and durable houses for the poor villagers particularly for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. (21)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[SHRI T. R. Ramanna]

[Need to give proper medical assistance in rural areas. (22)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to give compulsory education to the children in rural areas and adult education to the aged. (23)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to provide rural approach roads to all villages particularly those in the interior areas. (24)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to start agriculture-based industries in backward areas of the country. (25)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need for implementation of land ceiling laws and distribution of surplus land among the poor. (26)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need for giving reasonable compensation to those whose lands have been taken on account of land reforms. (27)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to help very small land holders, widows and unmarried daughters by giving them exemption under Land Ceiling Act. (28)].

"That the Demand under the Head Ministry of Rural Development be reduced by Rs. 100."

[Need to check agricultural land fragmentation. (29)].

श्री न. न. राय (गोपालमंज) :

मान्यवर, सदन में जो कृषि मंत्रालय की मांगें पेश की गई हैं, मैं उन का समर्थन करता हूँ।

हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 के साल को उत्पादन का साल घोषित किया है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी श्रीमती गांधी ने पहली, दूसरी एवं अन्य अधिकतम मदों में भी कृषि एवं कृषकों को से संबंधित काय, जोड़ कर रखा है। सिंचाई क्षमता में और वृद्धि तथा सूखी जमीन पर पानी से संबंधित तकनीकी जानकारी तथा उपकरण आदि तैयार करा कर किसानों तक पहुंचाने का निश्चय किया है तथा तिलहन दलहन आदि का उत्पादन बढ़ाने का संकल्प किया है इससे स्पष्ट होता है कि हमारी प्रधान मंत्री किसानों के उत्थान एवं उन्नति के लिये कितनी चिंतित हैं।

किसान भी इंदिरा जी के ऐलान को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना कर उत्पादन कार्य में जी जान से जुझ पड़े हैं। कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है। इस लिये किसान भाइयों के प्रति हम सबों की एक खास जिम्मेवारी है। उनके लिये आर्थिक विकास, रहन-सहन के स्तर में सुधार तथा कृषक परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। गांवों में कृषि विकास, उद्यान विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, परिवार कल्याण, आधुनिक सुलभ शिक्षा, यातायात की सुविधा, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था आदि पर विशेष बल देना होगा। आज भी करीब 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। खेती के योग्य जमीन लगभग 40 करोड़ एकड़ होगी और जनसंख्या 67 करोड़ हो गई। अतः प्रति व्यक्ति खेत दो बटा तीन एकड़ से कम ही पड़ेगा।

राष्ट्रीय आय में कृषि से 40 प्रतिशत आती है तथा निर्यात में 60 प्रतिशत की आमदनी कृषि उत्पादन तथा कृषि पर आधारित उद्योग के जरिये होती है !

वर्तमान में कृषि पदार्थों का मूल्यांकन एवं पणन की नीति गलत है तथा कृषि कार्य के लिये समयानुकूल नहीं है। यह नीति उस समय की है जब देश में खाद्यान्न बाहर से आता था तथा देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम था। उस समय खुले बाजार में खाद्यान्न के दाम अधिक थे और उपभोक्ताओं को संरक्षण की आवश्यकता थी। आज हमारे देश में उत्पादन बढ़ने से पैदावार खपत से ज्यादा होने लगी है। अतः वर्तमान समय में उत्पादनों को संरक्षण मिलना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने उत्पादकों के संरक्षण का वचन भी दिया है। वर्तमान कृषि नीति में देश में उपलब्ध कृषि विस्तार के लिये मौजूद साधनों का समन्वय नहीं किया गया है। इस में बहुत तर्क की आवश्यकता नहीं है कि जिस समय खाद्यान्न की कमी थी तथा आज उत्पादन बढ़ा है इन दोनों हालतों में भिन्न भिन्न तरीका अपनाना होगा। वरना ज्यादा पैदावार के फलस्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे पणन, मार्केटिंग, स्टोरेज प्राइज सपोर्ट, प्रोसेसिंग आदि की समुचित व्यवस्था भी करनी होगी। अन्यथा जो उत्पादन की तीव्र गति आई है वह अवरुद्ध हो जायेगी और किसान उदासीन हो जायेंगे।

गत वर्ष आलू का रेट 50 से 60 रुपये क्विंटल था और इस साल रेट घट कर तीस रुपये क्विंटल जब फरखाबाद में हो गया तो सरकार को सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने पर खरीद करना पड़ा जिससे किसानों को राहत मिली और फिर आलू का दाम 50 से 60 रु० क्विंटल हुआ। इस के लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। ऐसी स्थायी व्यवस्था करनी होगी

जिससे नई फसल आने के समय किसान को उचित दाम मिल सकें अन्यथा ट्रेडर उसका लाभ उठायेंगे।

यह दशा मीरचई, घनिया, प्याज, गुड़ आदि की भी हुई है और पारसाल से ये समान आधे दाम पर इस साल बिक रहे हैं किसानों को भारी धक्का लगा रहा है।

भारत में जमीन बहुत है, पानी है और सालों भर मिलने वाली सूर्य की रोशनी है। करीब करीब हमारी खेती वाली जमीन अमेरिका की खेतीवाली जमीन के बराबर है। दुनिया में मेरा सिंचाई सिस्टम बहुत बड़ा है तथा हमारे देश में दुगना पैदावार बढ़ाने की क्षमता मौजूद है। मेरे देश में सालों भर फसलें उगती हैं। हमारे वैज्ञानिक एवं तकनीशियनों की मांग विदेश में भी है। हमारे पास प्राकृतिक साधन भी हैं। मेरे नये बीज, ट्रैक्टर, पम्प, डीजल इंजिन आदि बाहर भेजे जा रहे हैं। हम भारत की एक मुख्य कृषि उत्पादन का देश बन सकते हैं और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न निर्यात कर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। तब हम किसानों को लाभप्रद मूल्य भी दे सकते हैं और उनकी हालत में सुधार इन्दिरा जी के संकल्प को अमलीजामा पहना कर कर दिखा सकते हैं। पंजाब में हम प्रदर्शित कर के दिखा दिये हैं कि भारत के औसत पैदावार से तिगुना, चौगुना, पैदा हम किये हैं। भारत के खेती की जमीन का केवल तीस प्रतिशत पंजाब में है परन्तु देश के पैदावार का 10 प्रतिशत पंजाब में उत्पादन होता है।

यह स्पष्ट है कि भारत में कृषि पर पहले बहुत जोर नहीं दिया गया। समाज में भी खेतीहरों की उतनी इज्जत के स्थान उन्हें पहले नहीं दिये गये तथा

[श्री नगीता राय]

कृषि उत्पादन के मूल्यांकन में उनकी बातें कम सुनी गईं। बराबर शहरी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा गया।

यह स्पष्ट है कि पूंजी की भूख से भारत की खेती बराबर तड़पती रही। यहां आधुनिक खेती के लिये 8 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर चाहियें। अभी केवल 10 प्रतिशत खेती ही आधुनिकतम हुई है, जिसे वाद करने पर (142-14) गुणा 8000 मिलियन-1024 बिलियन रुपया चाहिए।

भारत के किसानों की हालत उस मरीज के बराबर है जिसे खून बहने के कारण खून चढ़ाया जा रहा हो और जितना खून दिया जा रहा हो उस से ज्यादा खून शरीर से बाहर निकल रहा हो। जो खर्च कृषि पर हो रहा है उसमें ज्यादा नुकसान एवं लीकेज में चला जा रहा है और 50 प्रतिशत का ही लाभ किसानों तक पहुंच पा रहा है। भारत का साधारण किसान जब सीमित साधन के आधार पर सोचता है कि खेती के लिये आधा बोरा यूरिया खाद खरीदें या स्त्री की फटी चिथड़ी साड़ी के बदले एक नई साड़ी खरीदें। आधुनिक नया बीज खरीदें या बच्चे की पढ़ाई का खर्च दें। तब वह फसला लेता है कि साड़ी खरीदे और पढ़ाई के लिए रुपया दें। किसान अपने उत्पादित सामानों को बेच कर जो सामान उपभोक्ता-वाला खरीदता है उसमें उसे ज्यादा अनुपात में खर्च पड़ता है।

सरकार अपने बड़े मात्रा के बफर स्टॉक पर 650 करोड़ रुपया खर्च कर लागत से कम दाम पर बेचती है तब साधारण किसान को जिसमें माल रखने की क्षमता, आर्थिक कसबोरी के कारण नहीं है तथा स्टोरेज की सुविधा के अभाव में डिस्ट्रेस सेल कम दाम में

करना पड़ता है। आयात की असुविधा से अन्न को बाहर भेजना कठिन हो जाता है। अतः आप देखते हैं कि गेहूं इसी देश में 135 रुपए से 225 रुपए क्विंटल तक एक कोने से दूसरे कोने में बिकता है।

निर्यात-आयात की कुंजी भी दूसरों के हाथ में रहने के कारण जो फसला होता है, उससे किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। भारी रकम सरकार अन्न को सबसीडाइज रेट में उपभोक्ताओं को देने में लगाती है, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। प्रतिवर्ष 650 करोड़ सबसीडी दी जाती है, उसका लाभ मुख्यतः एफ. सी. आई. उठाता है। शार्टेज या बरबादी में एफ. सी. आई. उस सबसीडी का इस्तेमाल करती है।

देश में कृषि उत्पादन में तेजी आई है और भारत सरकार का ध्यान इस तरफ गया है तथा कृषि मद में आबंटन में वृद्धि की गई है। भारत में कृषि के मद में 82-83 में 1143 करोड़ रुपए का प्रावधान है जबकि 81-82 में 945 करोड़, 80-81 में 741 करोड़ था। देश के कई भागों में प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूब भी देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न 134 मिलियन टन पैदा हुआ, जबकि 80-81 में 129.9 मिलियन टन पैदावार था और 79-80 में 109.7 मिलियन टन था। अब 1982-83 में 141 मिलियन टन पैदावार की संभावना है। गन्ने की पैदावार भी 1981-82 में 170 से 180 मिलियन टन की संभावना है। जबकि 80-81 में 15.05 मिलियन टन था तथा 79-80 में 129 मिलियन टन था।

दलहन एवं तिलहन में भी काफी वृद्धि हुई है। पांचवीं योजना (74-79)

के काल में जहां तिलहन पर 14 करोड़ की राशि का उपबन्ध था वहां छठी योजना में 65 करोड़ का उपबन्ध किया गया है। जहां दलहन पर पांचवीं योजना में 12 करोड़ की राशि थी, वहां छठी योजना में 17 करोड़ का उपबन्ध किया गया है।

तिलहन 81-82 में 112 लाख टन पैदा हुआ जहां 80-81 में 94 लाख टन था। 82-83 में 120 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। दलहन 1981-82 में 125 लाख टन पैदा हुआ जहां 80-81 में 112 लाख टन था और 82-83 में 135 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है।

उन्नत बीज पर भी जोर दिया गया है। छठी योजना में 40.86 करोड़ रुपए का उपबन्ध है, जबकि पांचवीं योजना में 14.6 करोड़ था। जहां 79-80 में 14 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड दिया गया वहां 81-82 में 30 लाख क्विंटल और 82-83 में 40 लाख क्विंटल का लक्ष्य है।

कृषि पर ऋण का स्रोत आर.बी.आई है और कोआपरेटिव तथा कमर्शियल बैंक हैं। कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से जहां 60-61 में 214 करोड़ रुपए था वहीं 1980-81 में 1942 करोड़ हो गया।

सहकारिता के माध्यम से

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	एस. टी.	टर्म लोन क्रेडिट	टोटल
1980-81	1456	486	1942
1981-82	1703	553	2256
1982-83	2082	682	2764

कृषि के लिए सहकारी बैंक एवं कमर्शियल बैंकों को मिलाकर 1980-81 में 3377 करोड़ रुपए है और 1981-82 में 3800 करोड़ है।

खाद :-

खाद का दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों ने 1981-82 में 61.3 लाख टन खाद का इस्तेमाल किया जो पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि 4.9 प्रतिशत की वृद्धि 1980-81 में थी और 2.7 प्रतिशत की वृद्धि 1979-80 में थी। देश में भी खाद के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जहां 1980-81 में 30 लाख टन का उत्पादन हुआ वहीं 1981-82 में 41 लाख टन का उत्पादन हुआ। इससे आयात में कमी हुई और विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

खाद की 49 प्रतिशत बिक्री सहकारिता के माध्यम से है।

कीटनाशक दवाएं :-

प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम में जहां 1980-81 में 45000 टन दवा इस्तेमाल की गई वहीं 1981-82 में 50000 टन दवा का इस्तेमाल हुआ।

दुग्ध उत्पादन जहां 1951 में 17.4 मिलियन टन था वह अब 81-82 में 33 मिलियन टन पर पहुंच गया है।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि हमारी खेती अधिक उत्पादन के रास्ते में अग्रसर है। परन्तु हमारे किसान भाइयों के इन्पुट्स के दाम ज्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण खेती लाभप्रद नहीं हो पा रही है।

इंडेक्स आफ प्राइसेस आफ एग्रीकल्चर इन्पुट्स में अगर गेहूं का मूल्य 1971 में 100 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाए तो वह 1981-82 में 171.1 रुपए हो गया तथा उसी स्तर पर बिजली

[श्री नगोना राय]

1971 में 101.0 थी वह बढ़कर 246.4 हो गई। ट्रेक्टर्स 1971 में 109.6 था वह 1981 में 301.9 हो गया है। उर्वरक जो 1971 में 100.3 था वह 1981 में बढ़कर 259.5 हो गया। कीट नाशक दवाएं जो 1971 में 102 थीं वे बढ़कर 341.9 हो गईं। लुबरिकेटिंग आयल जो 98.5 थे बढ़कर 404.4 हो गए। पिग आयरन जो 100.8 था वह बढ़कर 303.8 हो गया। अतः इनपुट के दामों में बड़ी वृद्धि हुई है। वे दुगुने और तिगुने हो गए हैं। कृषि कार्य के लिए बैंक ऋण पर सूद की दर 14 प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक हो गई है जबकि दुनिया में कृषि के लिए बैंक दर बहुत कम है। थाइलैंड में 1 प्रतिशत तथा जापान, कौरिया मलेशिया फिलिपींस आदि में 3 से 4 प्रतिशत सूद पर खेती के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध हो जाता है। अतः सूद की बैंक दर कम होनी चाहिये।

चीनी का उत्पादन 1980-81 में 51.5 लाख टन हुआ जबकि 1979-80 में 38.9 लाख टन हुआ था। 1981-82 में 70 लाख टन होने की संभावना है। 8.5 रिक्वरी के आधार पर मिनिमम प्राइस 13 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है जो लेवी शूगर के मूल्यांकन का बेस रह है। ए पी सी ने 15.5 रुपये प्रति क्विंटल की मिनिमम प्राइस बेस रख कर लेवी शूगर का दाम निर्धारित करने के लिए अनुशंसा की है। क्षमता उपयोग में सुधार लाना छठी योजना की सफलता का आधार है। क्षमता उपयोग पर प्रत्येक पूर्व योजना में बल दिया गया था किन्तु उस पर अमल नहीं हो सका। ऐसे समय जब साधन बहुत सीमित हो तब यह मांग करना सार्थक होगा कि उपलब्ध वित्तीय और पदार्थ सम्बन्धी साधनों का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाए ताकि उन से अधिकतम प्राप्ति

हो सके। बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी कि उपलब्ध साधनों से कृषि क्षेत्र में मौजूदा सम्पत्ति में वृद्धि हो। इसका अर्थ है कि चीनी उद्योग और उसके भावी विकास, इसके पुनर्संचालन, आधुनिकीकरण और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान बड़ी संख्या में गन्ना उगाते हैं। गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जिस सहयोग की आवश्यकता होती है वह उन्हें मिल नहीं रहा है और न मिला है। इस क्षेत्र में उगने वाले गन्ने की किस्म में लंबे समय से कोई सुधार नहीं हुआ है। जल क्रांति और पानी के विकास की अनुविधा के कारण गन्ने का उत्पादन कम है और परिणामस्वरूप चीनी मिलों में—क्षमता उपयोग भी कम है। 1965 में ही सेन चीनी जांच आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था। इसका विचार था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और बिहार के उत्तरी जिले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इन में खनिज भंडार नहीं है। दूसरे शब्दों में यहां महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध नहीं है जिस के आधार पर बड़े उद्योग लगाए जा सकें। संतुलित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों को निर्धारित से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिये। कम माल पहुंचने के कारण ये मिलें क्षमता से कम माल तैयार करती हैं। यह न्याय संगत होगा कि उपलब्ध साधनों के अनुसार इन्हें कुछ अतिरिक्त सहायता दी जाए जिससे कि गन्ने का उत्पादन बढ़े, उससे उपलब्धता और माल भ्रष्टा निकले ताकि देश में सीमित साधनों का न्यूनतम उपयोग करने पर अनुकूल प्राप्ति हो सके। प्राथमिकताओं का उपयुक्त निर्धारण करके गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग को प्रोत्साहन, आधुनिकीकरण और पुनर्संचालन के लिए संयुक्त और समन्वित प्रयत्न करने होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा नई नई चीनी मिलों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव निराशाजनक है। छठी योजना के दौरान योजना आयोग ने चीनी उद्योग के लिए एक कार्य दल

का गठन किया है। 82 नई इकाइयाँ होंगी और 55 मिलों का विस्तार किया जाएगा। नई इकाई पर 656 करोड़ और विस्तार पर 220 करोड़ अर्थात् 876 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। विस्तार को प्राथमिकता मिलनी चाहिये क्योंकि यह कम खर्चीला है तथा शीघ्र लाभ देने वाला होता है। अगर छठी योजना में नई इकाइयों और विस्तार अनुपात को 25:75 कर दिया जाए तो लगभग 101 करोड़ की बचत होगी। साथ ही वही उद्देश्य वर्तमान फैक्ट्रियों का विस्तार कर उन्हें जरूरत भर मात्र की आपूर्ति करके और किसानों की हालत में सुधार करके पूरा किया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को यह वरदान प्राप्त है कि यहां की मिट्टी में स्वाभाविक नमी मौजूद है और गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी विद्यमान है। भारत में ही सब से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग की शुरुआत हुई। 1930-1940 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के चीनी उत्पादन का 30.93 प्रतिशत और बिहार 40 प्रतिशत अर्थात् पूरे देश का 70 प्रतिशत उत्पादन होता था। इस क्षेत्र में गन्ना एक मुख्य नकदी फसल है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मेरु दंड है। यहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 250 रु० है जब कि देश की औसत आय 690 रु० है। पूरे भारत में 113 चीनी मिलें विस्तार के लायक हैं। जिसमें 37 पूर्वी उत्तर प्रदेश की और 28 बिहार की हैं।

देश में चीनी उत्पादन की क्षमता 6 लाख टन है। कम उत्पादन के कारण 300 करोड़ रु० की हानि हर साल होती है और सरकार को 45 करोड़ रु० का घाटा उत्पादन शुल्क और दूसरे करों में होता है। अब महाराष्ट्र की 10 संयुक्त इकाइयों में भी घाटा आने लगा है और महाराष्ट्र में भी घाटे की

सीमा 45 करोड़ रु० तक पहुंच गई। इस आलोक में समता उपयोग की कमी को ध्यान में रख कर मौजूदा मिलों के आधुनिकरण एवं विस्तार को ही प्राथमिकता देनी चाहिये। नये मिलों की लाइसेंस देना न्याय संगत नहीं होगा। बन्द मिलों को भी चलाया जाय।

ए०पी०सी० का वही सुझाव यहां लागू होता है जो उपभोक्ताओं को सूट करता है और उत्पादकों के लिये इन-पुट्स का दाम कम करने का सुझाव जो ए०पी०सी० ने दिया है सरकार उस पर अमल नहीं करती है। लागत खर्च पर दाम की निश्चितता का रहस्य भी अजीब है। ए०पी०सी० ने खुद ही स्वीकार किया है कि दाम पूर्व वर्ष के खर्च के आधार पर तय होता है न कि वर्तमान वर्ष के खर्च की लागत पर। ए०पी०सी० की कमी भी खेती में जो रिस्क है उसका लेखा जोखा दाम तय करने में नहीं करता है, जब सभी जानते हैं कि बाढ़, सूखा, पत्थर, कीड़ों के प्रकोप एवं बीमारियों के चलते फसलें बरबाद होती हैं और यह मानव के कंट्रोल व शक्ति के बूते से बाहर हैं।

बिहार में विस्कोमान के पास 40 करोड़ की खाद पड़ी है जिस पर सूद की बड़ी रकम देना पड़ रहा है, सरकार उस सूद में अनुदान देकर इस सहकारी संस्था को घाटे से बचाये। मेरे सुझाव है कि :

1. ए०पी०सी० में वास्तविक किसानों का बहुमत रहे, जो खुद उत्पादन करते हों।

2. एस०टी०सी० की तरह एक अलग ऐग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की जाय जो केवल कृषि एवं कृषि पर आधारित

[श्री जमीना राय]

ग्रादिवासी क्षेत्र में 10,000 की जनसंख्या के आधार पर खोला जाये ।

सामानों का निर्यात करे तथा उस पर पूर्ण अधिकार रखे ।

12. छठी योजना में 5.50 करोड़ की लागत से जो उत्तरी पूर्वी रीजन में आधुनिक कृषि औजारों को बढ़ावा देने की स्कीम 1982-83 में चालू होने वाली है उसमें असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार को जोड़ा जाय ।

3. पूरे देश को एक जोन ट्रीट किया जाये और देश के एक कोने से दूसरे कोने में माल जाने आने में किसी तरह की रोक टोक नहीं रहे ।

4. धान के लिये डीप वाटर वेसि-स्टंग किस्म के धान का अनुसंधान हो जिससे लाखों एकड़ डूबी हुई जमीन में खेती हो सके ।

5. वैज्ञानिक एक्सटेंशन सेवा का विस्तार पंचायत लेवल पर हो और वही खाद, बीज, कीटनाशक दवा, उन्नत कृषि औजार, ऋण आदि प्राप्त हो जाय ।

6. क्राप इन्श्योरेंस स्कीम का विस्तार पूरे देश में किया जाय और खासकर उस क्षेत्र में जहां प्राकृतिक प्रकोप से फसलें बरबाद होती हैं ।

7. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये ठोस कदम उठाये जायें ।

8. किसानों को उचित एकोनोमिक एवं रेम्यूनरेटिव मूल्य मिले ।

9. स्टोरेज और मारकेटिंग की सुलभ व्यवस्था हो ।

10. कीट नाशक दवाइयों का फ्री स्प्रेडिंग हो जब कभी कीड़े बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र में आक्रमण करें ।

11. बिहार के लिये एक अलग बैंक रेक्यूमेंट बोर्ड की स्थापना की जाय, जैसा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है और ग्रामीण बैंक की 1482 शाखायें 20,000 की जनसंख्या पर खुली हैं, उसे छोटा नागपुर एवं संधाल परगना

13. आर. डी. आई. एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा राशि आवंटित करे ।

14. लाखों की संख्या में तरुण एवं उपयोगी गौवंश जो काटा जा रहा है उस पर गम्भीरता से विचार हो, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं ।

उपरोक्त मुद्दाओं के साथ मैं प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृषि के लिये विशेष ध्यान रखा जाये, क्योंकि किसानों की आंखें आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रही हैं ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) :
उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो प्रगति की है, उसके लिये हमें, हमारी सरकार, हमारे किसानों और वैज्ञानिकों को, सभी को गर्व है कि हम कृषि के उत्पादन में सेल्फ सफीशिएंट, आत्म-निर्भर हो चुके हैं । परन्तु आत्म-निर्भर होने से ही हमारा प्रयोजन सफल नहीं हो पाता, जब कि कि हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़ना चाहिये और यह स्थिति पैदा होनी चाहिये कि हमारे फूड स्टॉक की स्थिति साउंड होनी चाहिये । पहले 2 करोड़ टन फूड हमारे रिजर्व स्टॉक में था, किन्तु अब वह स्थिति नहीं है ।

इसलिये यह प्रयास किया जाना चाहिये कि रिजर्व में जितना भी फूड स्टॉक रखा जायेगा, उतना ही हम कीमतों पर कंट्रोल कर सकेंगे और हमारी कृषि की इकनामी व्यवस्थित हो सकेगी।

कुछ मुद्दों पर अपने विचार में रखना चाहता हूँ, खास तौर से जो रेगिस्तान से संबंधित हैं। डैजर्ट डैवलपमेंट का प्रोग्राम 1977-78 में शुरू किया गया जो कि सेंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम थी। एग्रीकल्चर कमीशन की रिक्न्डडेशन के अनुसार वह कार्यक्रम शुरू किया गया और उसकी आवश्यकता भी थी।

इसमें जो राशि का प्रावीजन किया गया है उसके मुकाबले डैजर्ट का एरिया इतना बड़ा है जिसमें अभी आपने 21 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल किये हैं। राजस्थान के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स उसमें सम्मिलित हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है जोकि हर तरह से सूखे से प्रभावित होते हैं। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, यह रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इसमें बाड़मेर और जैसलमेर हैं, जिनका मैं प्रतिनिधि हूँ। आपने जो प्रावीजन कर रखा है, वह अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपये सालाना का प्रावधान है। छठी पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ का और है। मेरा ही क्षेत्र केरल प्रान्त से डबल है, हरियाणा से ड्योडे से ज्यादा है, उसके बावजूद जोधपुर, जालौर डिस्ट्रिक्ट वगैरह 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन डैजर्ट्स को हम वलप डैकरना चाहते हैं, इसमें हरियाणा का भी क्षेत्र लिया है, हिमाचल, गुजरात, जम्मू-

काश्मीर का लद्दाख का एरिया भी इसमें लिया है।

जिस प्रकार से शिडूल्ड ट्राइब्ज एरिया के बारे में सेंट्रल की स्पेशल एसिस्टेन्स स्कीम हैं, उनका जो सब-प्लान बनाया गया है, इन एरियाज का भी सब-प्लान बना देना चाहिये। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे पाकिस्तान की सरहद हो, जम्मू-काश्मीर का लद्दाख का पोर्शन जो चीन-पाकिस्तान की सीमा पर है, उधर बाड़मेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सीमावर्ती हैं, कहने का अर्थ यह है कि एक तो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जिनका मोरल वूस्ट करना है, और दूसरी और डैजर्ट्स को विकसित करना है। जैसी शिडूल्ड ट्राइब्ज की स्थिति है, वही इन एरियाज की भी स्थिति है, चारों तरफ जब सूखा हो, तो इन लोगों की किस प्रकार की स्थिति होती है, इसलिये आवश्यक है कि इन एरियाज के लिये सेंट्रल स्पेशल एसिस्टेन्स स्कीम के अन्तर्गत सब-प्लान करके इसका प्रावीजन किया जाये। पहले 250 करोड़ रुपये का एक सब-प्लान बनाया जाये और उसके बाद राशि को सातवीं प्लान में और बढ़ाया जाये ताकि हम कह सकें कि हम कितने अर्से में इस डैजर्ट की समस्या को हल कर सकेंगे।

दूसरी बात फ़ैमिन की है। फ़ैमिन और फ़्लड के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may continue your speech the next day. The House stands adjourned till 11 a.m. Thursday, the 15th April.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, 15 April, 1982 Chaitra 25, 1904 (Saka).